



नागिन ने परिवार के 5 लोगों को डसकर बदला लिया? बाप-बेटे की हुई थी मौत; 3 दिन बाद सांप के वापस लौटने से शक गहराया, जानिए- सच

जयपुर करौली के मांची गांव में 3 दिन में 6 लोगों को सांप ने डस लिया। इनमें 5 एक ही परिवार के थे। पिता-पुत्र की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

लगातार सांप डसने के मामले सामने आने के बाद गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने सांप को ढूँढ़ कर मार डाला।

मामले को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं।

सांप एक परिवार से बदला लेने के लिए बार-बार आ रहा है।

नाग-नागिन के जोड़े में नाग की मौत हो गई। मारने वाले की फोटो नागिन की ओर से छप गई। वहीं बदला ले रही है।

सांप की याहाशत बहुत तेज होती है, वो अपना बदला कभी नहीं भूलता।

14 अक्टूबर : 'पुष्ट्र शिंग' (32) और उनका बेटा गवित (4) कमर में सो रहे थे। देर रात दोनों को सांप ने डस लिया। परिजन देवी सिंह ने बताया कि हम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। गवित को जयपुर रेफर कर दिया।

रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुष्ट्र की भी करौली अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

16 अक्टूबर : देवी सिंह के छोटे भारा बाबू सिंह, उनका बेटा दीपेंद्र (18) और भतीजा नागेंद्र (31) एक ही कमर में सो रहे थे। सुबह करीब पैसे चार बजे बाबू सिंह को शरीर पर कुछ रेगत हुआ महसूस हुआ। उन्होंने लाइट जलाई तो सांप दिखा। उन्होंने शोर मचाते हुए सांप को बाहर निकाल कर फेंका।

16 अक्टूबर : कोही सांप ने बाबू सिंह के परिवार के दीपेंद्र को और पड़ोस में रहने वाली महिला अकिंता (30) की भी डास। करौली अस्पताल के पीएमओ डॉ. रामकेश मीणा ने बताया कि राहत की बात रही कि जहर का असर कम था। इसी तरह गांव के बाबू सिंह भर्ती हुए, लेकिन उनके शरीर पर डसने के निशान नहीं मिले।

घटनाओं के पीछे किस प्रजाति का सांप था? घटना के बाद सांप को पकड़ने के लिए रवि मीणा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि डसने वाला सांप कोमन करेत के नाम से जाना जाता है।

ये सांप बहुत ही जहरीला होता है। इसे साइलेंट किलर की भी कहते हैं। सोते हुए व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। जैसे ही व्यक्ति कर-वर्त लेता है या कोई और करकर करता है तो डस लेता है। इसके दांत इतने बारीक होते हैं कि लोगों को डसने की अंदाजी नहीं होती है।

उनकी सोते-सोते ही मौत हो जाती है।

14 और 17 अक्टूबर की घटना के पीछे भी कॉमन करेत था, लेकिन उसने इन्हीं तो जहर पूरा पहुंच जाए।



क्या सांप एक-दूसरे की मौत का बदला लेते हैं?

सांपों का दिमाग का बहुत छोटा साइज और याद रखने की क्षमता कम होती है। इसका मतलब साफ है कि एक सांप किसी दूसरे सांप का बदला नहीं ले सकता।



क्या नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति का चेहरा सांप की यादाशत में रह जाता है?

इंसानों और जानवरों की तरह सांपों में भी दिमाग होता है, लेकिन बहुत बेसिक। तकनीकी तौर पर कहा जाए तो सांप का दिमाग उसके शरीर का केवल 1 प्रतिशत हिस्सा (भार या वजन) है। सांप कुरुंच-बिल्ली जैसे जानवरों की तरह इशारे नहीं समझ सकता। हालांकि सांप खतरा भायं सकता है। बचाव के लिए अकमण कर सकता है। नर सांप मादा को और मादा नर को पहचान सकती है। | कुछ पलों के बाद संबंधित घटना उसे याद नहीं रह सकती। ऐसे में ये भी तय है कि सांप खुद को नुकसान पहुंचाने वाले की चेहरा याद नहीं रख सकता।

सांप बार-बार एक ही घर में आकर क्यों डस रहा है?

इसे इस तरह समझ सकते हैं कि सांप किसी जगह से निकलता है मार्किंग के लिए अपनी गंध छोड़ता जाता है। सांप अपनी जीभ के जरिए गंध को सूंध सकते हैं। सांपों की सूंधने की क्षमता इंसान से हजारों गुना अधिक होती है। नर और मादा सांप में सांप में सांप में यह जिनाइल-डिलोल से धोने पर भी कुछ दिन तक नहीं जाती है। | गंध इतनी सूक्ष्म स्तर (माइक्रो) की होती है कि फिनाइल-डिलोल से धोने पर भी कुछ दिन तक नहीं जाती है। सांप एक दूसरे की गंध पा कर यांत्रिक करते हैं। ऐसे में सांप उस घर तक पहुंच जाते हैं, जहां कुछ दिन पहले सांप आ चुका होता है। यदि कुछ दिन पहले उस घर में किसी सांप को मारा हो तो फिर अफवाह फैल जाती है कि सांप का बदला लेने के लिए उसका जोड़ीदार आया है। जबकि वह पुराने सांप की गंध से आकर्षित होकर संबंधित घर में पहुंचता है।

दांत नहीं गड़ाए थे कि डसने वाले के शरीर में जहर पूरा पहुंच जाए।



क्या सांप देख और सुन सकते हैं?

सांप इंसानों या अन्य जानवरों की तुलना में बहुत दूर तक नहीं देख पाते। कुछ सांप साफ देखते हैं तो कुछ धृधला देख पाते हैं। सांपों के इंसानों और अन्य जानवरों की तरह बाहरी कान नहीं होते हैं। वे अन्य जीव के चलने से धर्ती में होने वाले बाव्हाशन को महसूस करते हैं। जब भी कोई बीन बजाता है तो लोगों को लगता है कि सांप बीन की धून पर नाच रहा है। हकीकत में सांप अपने बचाव और आकमण के लिए फन को बीन की ओर उठाता है।

सांप काटे तो कैसे पता करें कि वह जहरीला है या नहीं?

डसने पर यदि दो डंके के निशान बनते हैं तो समझ लीजिए कि सांप जहरीला है। काटने वाले स्थान के आस-पास एक नाला धोरा भी बन जाता है। ऐसी सिहुराशन हो तो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचें। वहीं यदि सांप के काटने पर दो दांत के बजाय चंद्राकार के छोटे-छोटे काटने के निशान बनते हैं तो इसका मतलब कि सांप जहरीला नहीं है। लेकिन सावधानी के तहत अस्पताल जरूर जाएं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज लें।

87 किलो गंजे के साथ 2 गिरफ्तार:

मुख्यमंत्री की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश, मकान में प्लास्टिक के कट्टों में मिला

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा। अवैध मादक पदार्थों की धर पकड़ के लिए भीलवाड़ा जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर एक मकान से बड़ी मात्रा में अवैध गंजा बरामद कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुर थाना प्रभारी जय सुलतान ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में एसपी धर्मदंसिंह यादव के निर्देश और एडिनगनल एसपी पारसमल जैन के निर्देश में अवैध मादक पदार्थों की धर पकड़ के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत जिले की मुख्यमंत्री से गिरफ्तार के लिए लगातार सांपत्तिक बाबू के अंजाम देकर एक मकान से 87 किलो 320 ग्राम गंजा बरामद किया और दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुर थाने के एसआई गोपाल लाल को मुख्यमंत्री से सूचना मिली थी कि कोटडी गंज में दो व्यक्ति संदिध धूम रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पुर हुंची और इनसे पूछताछ की तो दोनों ही घबरा गए।

10 हजार की रिश्वत लेते हैं डॉक्टर एसीबी ट्रेप:

FIR से नाम काटने की एवज में 20 हजार की डिमांड की थी, जयपुर एसीबी की मानपुर थाने में कार्रवाई

द पुलिस पोस्ट

दौसा। जयपुर एसीबी की टीम ने दौसा जिले के मानपुर पुलिस थाने में कार्रवाई करते हुए हैंड कास्टेबल को रिश्वत लेते हैं ट्रेप किया है। परिवारों ने शिकायत की एवज में हैंड कास्टेबल अजीत सिंह 20 हजार की डिमांड कर रहा है। जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर गुरुवार अपराह्न थाने के दबिश देकर ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर एसीबी के एसपी पुष्ट्र-न्द्रिंश डिलीप ने एक घूमकेतु के नेतृत्व में टीम की कार्रवाई करते हुए हैंड कास्टेबल अजीत सिंह को लेकिन दौसा जिले के रिश्वत लेते रहे हाथों ट्रेप किया है। पुलिस थाने में अचानक पहुंची भ्रष्टाचार निरोधक व्यूहों की टीम को देख वहां मौजूद पुलिस कर्मियों में खलबली मच गई। ट्रेप की कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम ने पुलिस थाने में लोगों की आवाजाही को पूरी तरह बंद रखा।

'मम्मी-पापा खुश रहो' लिखकर फंदे पर झूला नीट स्टूडेंट:

बहन गेट खटखटाती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला; कोटा में इस साल 13 आत्महत्याएं

द पुलिस पोस्ट

कोटा। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एक और स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। बुधवार देर रात हुई सुसाइड की यह घटना शहर के दादाबाबा थाना इलाके की है। स्टूडेंट ने पौरी जीवन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शब्द फंदे से उत्तरा। उत्तर प्रदेश के मिजारुपुर का रहने वाला स्टूडेंट अपनी ब



कन्या भ्रूण हत्या रोकने
हेतु जागरूकता रैली
आयोजित



द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा सेठ मुरलीधर माहिला अधिकारी कन्या भ्रूण हत्या में रोकने के लिए पीसीएनडीटी एक्ट पर एक रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को प्राचार्य डॉ सावन कुमार जामिणी ने रोका किया। यह रैली महाविद्यालय से अरंग होकर बड़ा चौराहा होते हुए पुनः महाविद्यालय पहुंची। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ सीमा गोड़ ने बताया कि रैली का मुख्य लक्ष्य पीसीएनडीटी एक्ट से आमजन को जागरूक करना व कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था। जिससे समाज में लैंगिक समानता बढ़ी रहे एवं गिरते हुए लैंगिक अनुपात को रोका जाए। महिला प्रकोष्ठ सदस्य इका श्री वर्मा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर महिला प्रकोष्ठ के समर्त सदस्य, महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्य एवं लगभग 45 छात्राएं उपस्थित रही।

**पूर्व महिला विधायक को भेजे
अश्लील मैसेज, रेप की धमकी:
वॉट्सऐप पर लिखा- तेरा
हाल भी बाबा सिद्धीकी के
जैसा कर दूंगा**



द पुलिस पोस्ट

जालोर। जालोर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल (39) को जान से मारने की धमकी के साथ वॉट्सऐप पर अश्लील मैसेज मिले हैं। मेघवाल ने इस संबंध में यहां पुलिस आयुक्तालय के साइबर थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार उनके वॉट्सऐप पर 7480713982 नंबर से अश्लील मैसेज और एक कॉल भी आई है। उस नंबर पर वापस कॉल किया तो सामने वाला व्यक्ति गालियां देते हुए कहा कि तेरा हाल भी बाबा सिद्धीकी के जैसा कर दूंगा। अरोपी ने पूर्व विधायक को रेप की भी धमकी दी। मामला दर्ज होने के बाद भी उस नंबर से कॉल और मैसेज आ रहे हैं।

**पूर्व में भी धमकी मिली,
हमले भी हुए**

मेघवाल ने बताया कि उनके साथ पिछले कुछ सालों से ऐसी घटनाएं होती रही हैं। जयपुर में उन्हें पहले भी धमकाया गया था, इसे लेकर सोडाला थाने में रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा उन पर 2021 व 2022 में 2 बार हमले भी हुए हैं। इसको लेकर जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में उन्होंने मामला दर्ज कराया था। हाल ही में 8 जुलाई को जालोर में उनका ससुराल पक्ष से विवाद हो गया था। इस पक्ष वाबूलाल, ससुर हेमाराम, चाचा ससुर शिवलाल सोलंकी और देवर कैलाश के विरुद्ध मारपीट करने के साथ दर्ज किया गया था।

**एडवोकेट पति बाबूलाल
से हो चुका है तलाक**

अमृता मेघवाल की शादी जालोर जिले के नोरा हाल रामदेव कॉलोनी निवासी एडवोकेट बाबूलाल मेघवाल पुत्र हेमाराम मेघवाल से 21 अप्रैल 2008 को हुई थी। अमृता चांगोद (पाली) की रहने वाली है। 21 जनवरी 2019 को दोनों के बीच इतना विवाद हुआ कि वे अलग रहने लगे। करीब 3 साल बाद पति बाबूलाल ने फैमिली कोर्ट जालोर में तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दर्खिल किया। कोर्ट ने अमृता मेघवाल को कई नोटिस भेजकर उपरिथित होने को कहा, लेकिन वे कोर्ट में उपरिथित नहीं हुईं। इस पत्र कोर्ट ने 4 मई 2023 को तलाक का फैसला बाबूलाल के पक्ष में दे दिया।

जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक सम्पन्न

परिवादों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करें- एडीएम मेहरा

**जनसुनवाई में परिवादियों
को मिली राहत**

**सतर्कता के 10 प्रकरण
और जनसुनवाई के 93
परिवाद सुने**

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा, राज्य सरकार के निदेशों की पालना में जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील बातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला कलकटर निमित्त मेहता के निदेशन्सुनारा अतिरिक्त जिला कलकटर प्रशासन ओमप्रकाश मेहरा की अध्यक्षता में भाह के तीसरे गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति की बैठक सूचना पौद्योगिकी एवं संचार विभाग के बीच हॉल कलेक्टर परिसर में आयोजित हुई। इस अवसर पर महिला प्रकोष्ठ के समर्त सदस्य, महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्य एवं लगभग 45 छात्राएं उपस्थित रहीं।



संबंधित अधिकारियों को उनके परिवादों से त्वरित व समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलकटर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए लंबित प्रकरणों को त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। अति. जिला कलकटर ने कहा कि सभी अधिकारी न सिर्फ संख्यात्मक बल्कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से परिवादों का संवेदनशीलता से निस्तारण कर अधिक से अधिक लोगों को राहत प्रदान करें। जिला जनसुनवाई में गिरधरुरा विजेतिया निवासी बजरंगदास पिता धीसादास ने बिजली कनेक्शन में विलंब का परिवाद रखा। परिवादी ने बताया कि विद्युत केनेक्शन के लिए उसके द्वारा डिमांड राशि जमा करवा दी गई है। ठेकेदार द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए पैसे की मांग को जा रही है। एडीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा परिवादी के विद्युत कनेक्शन करवाने के लिए निर्देशित किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावलास के खेल मैदान पर अतिक्रमण संबंधी परिवाद पर एडीएम ने सीमा ज्ञान कराकर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। जांच अधिकारी ने बताया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार निजी खातेदारी भूमि होने से निगम द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती। एडीएम ने वैकल्पिक रास्ता देने संबंधी बात कही। बुजुंग महिला प्रार्थी के मारपीट संबंधी परिवाद पर एडीएम ने उपर्खंड अधिकारी को तहलसीदार के साथ भौका विजिट कर आवश्यक किया। जांच अधिकारी ने निर्देश दिए। जिला सुनवाई में सरकारी भूमि व



कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया। पुर निवासी परिवादी विजय कुमार के प्रकरण जिसमें सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर पथर आया है। एडीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा परिवादी के विद्युत कनेक्शन करवाने के लिए निर्देश दिए। जांच अधिकारी ने बताया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार निजी खातेदारी भूमि होने से निगम द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती। एडीएम ने वैकल्पिक रास्ता देने संबंधी बात कही। बुजुंग महिला प्रार्थी के मारपीट संबंधी परिवाद पर एडीएम ने उपर्खंड अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। जिला सुनवाई में सरकारी भूमि व

सार्वजनिक स्थानों से स्थाई, अस्थाई तथा अवैध अतिक्रमण हटाने, सीमा ज्ञान करवाने, पष्टे जारी करने, सड़क निर्माण, पारिंग व्यवस्था तुरुस्त किए जाने, पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने, पथरगढ़ी करवाने समेत अन्य राजस्व प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिसके समाधान के लिए एडीएम मेहरा ने प्रकरणों की जांच कर परिवादियों को राहत पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। बैठक में यूआईटी ओएसडी चिमन लाल भीणा, नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी, पीडल्यूडी एक्साइरन नरेंद्र चौधरी सहित बिजली, पानी सहित अच्युत विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी समेत उपर्खंड तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी से जुड़े।

भजनलाल सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए गंभीर प्रयास

**मंडी श्रमिकों को
योजना के तहत
चिकित्सा, शिक्षा एवं
विवाह हेतु आर्थिक
सहायता**

द पुलिस पोस्ट



एवं ह्याअच्यु श्रेणी की मंडियों द्वारा प्रति श्रमिक 1000 रुपये, ह्यावह्य श्रेणी की मंडियों द्वारा 500 रुपये, ह्यासह्य श्रेणी की मंडियों द्वारा 300 रुपये और ह्याद्वाह श्रेणी की मंडियों द्वारा 200 रुपये प्रति श्रमिक अंशदान जमा करवाया जाता है।

**लाडली के विवाह पर
50 हजार रुपये की
सहायता**

योजना के तहत अधिकारी ने विवाह पर 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। योजना के माध्यम से उन्होंने अल्जितारी के लिए विवाह पर 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। योजना के माध्यम से उन्होंने अल्जितारी के लिए विवाह पर 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। योजना के माध्यम से उन्होंने अल्जितारी के लिए विवाह पर 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।

**श्रमिकों को 20 हजार
रुपये की चिकित्सा
सहायता**

अनुज्ञासिधारी हमाल एवं पल्लेदारों को कैसर, हार्ट एटैक, लीवर, फिडनी जैसी गंभीर बीमारियों से प्रसिद्ध होने पर सरकारी अस्पताल, च्वास्थ एवं रक्तांतर के लिए अधिकृत अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा सहायता के लिए अधिकृत अस्पताल के लिए अधिकृत अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा सहायता के लिए अधिकृत अस्पताल के लिए अधिक

संम्पादकीय

न्याय की गांधारी की आँखों से पट्टी का हटना सुखद

क हते हैं की जो होता है सो अच्छा ही होता है। भारत में न्यायपालिका का प्रतीक चिन्ह आँखों पर पट्टी बंधे हाथ में तलवार लिए एक स्त्री का चित्र था। इसे न्याय की देवी कहा और माना जाता है, क्योंकि न्याय देने का काम शायद देवता नहीं कर पाते हैं। न्याय की देवी की आँखों पर पट्टी शायद इसलिए बंधी गयी होगी ताकि वो नीर-क्षीर विवेक से न्याय कर सके, हाथ में तलवार शायद इसलिए दी गयी होगी ताकि वो निर्ममता से ढंड दे सके, लेकिन अब उसकी आँखों से पट्टी भी हटा दी गयी है और हाथ से तलवार भी छीन ली गयी है। न्याय की देवी के हाथों में उस सर्विधान की प्रति पकड़ा दी गयी है जो हाल के आम चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और बाकी का विपक्ष लेकर घूम रहा था।

न्याय की देवी की वास्तव में यूनान की प्राचीन देवी है, जिन्हें न्याय का प्रतीक कहा जाता है। इनका नाम जस्टिया है। इनके नाम से जस्टिस शब्द बना था। इनके आंखों पर जो पट्टी बांधी रहती है, उसका मतलब है कि न्याय की देवी हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करेगी। किसी को देखकर न्याय करना एक पक्ष में जा सकता है। इसलिए इन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी थी।



हम सब इसका स्वागत करते हैं। इस समय जिस भा
व्यवस्था की आँखों पर पट्टी बंधी हो उसे हटाने की जरूरत
है। आँखों पर पट्टी का बंधा होना जहाँ नीर-क्षीर विवेक का
प्रतीक माना जाता रहा है वहीं इसे जानबूझकर आँखें बंद
करने का प्रतीक भी माना जाता है। द्वापर में गांधारी ने अपनी
आँखों पर पट्टी अपने पति प्रेम के चलते बांधी थी, लेकिन
उसका क्या परिणाम हुआ, पूरी दुनिया जानती है। दुनिया
न भी जानती हो, लेकिन भारत का बच्चा - बच्चा जानता
है। सुप्रीम कोर्ट के इस नवाचार का हम दिल खोलकर
स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि अब देश में न्यायप्रणाली
की आँखें न सिर्फ खुली हों बल्कि गंगाजल से धुली भी हों।
अभी तक भारतीय न्यायपालिका में देश का भरोसा कायम
है यद्यपि न्यायपालिका तमाम आधे-आधेरे फैसलों की वजह
से समीर हुई है तथापि उसे अनेक फैसलों की वजह से
पूरा सम्मान भी हासिल है।

नहीं होता। वो सबको समान रूप से देखता है। इसलिए न्याय की देवी का स्वरूप बदला जाना चाहिए। साथ ही देवी के एक हाथ में तलवार नहीं, बल्कि सर्वधान होना चाहिए; जिससे समाज में ये संदेश जाए कि वो सर्वधान के अनुसार न्याय करती हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब का मानना है कि तलवार हिंसा का प्रतीक है। जबकि, अदालतें हिंसा नहीं, बल्कि संवेद्धानिक कानूनों के तहत इंसाफ करती हैं। दूसरे हाथ में तराजू सही है कि जो समान रूप से सबको न्याय देती है।

हन उम्मीद बरो पाहाएँ पा जित तरह राना आपु अज
नयायधीश ने अपनी सेवा निवृत्ति से कुछ दिन पहले
न्यायपालिका के प्रतीक को बदला है उसी तरह वे जाते-
जाते उन सभी संवैधानिक संस्थाओं की आँखों पर बंधी पट्टी
और हाथों में ली गयी दृश्य और अवश्य तलवारों को
हटवाने का भी इंतजाम कर जायेगे। इडी हो, सीबीआई हो
या केंद्रीय चुनाव आयोग हो सबकी आँखों पर पट्टी और
हाथों में तलवार है। आज का युग आँखों पर पट्टी बांधकर
काम करने का है भी नहीं। आज के युग में तलवार हाथ में
लेकर दुनिया को नहीं चलाया जाता। आज कीदुनिया के
हाथों में तलवार की जगह विनाशकारी बम आ गए हैं,
मिसाइलें आ गयी हैं, जो सामूहिक नरसंहार कर रहे हैं।
हमारे कानून के शिक्षक स्वर्गीय गोविंद अग्रवाल साहब हमे
पढ़ते वक्त बताया करते थे कि -न्याय की देवी की वास्तव
में यूनान की प्राचीन देवी हैं, जिन्हें न्याय का प्रतीक कहा
जाता है। इनका नाम जारिस्या है। इनके नाम से जरिस शब्द
बना था। इनके आँखों पर जो पट्टी बंधी रहती है, उसका
मतलब है कि न्याय की देवी हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय
करेंगी। किसी को देखकर न्याय करना एक पक्ष में जा
सकता है। इसलिए इन्हनें आँखों पर पट्टी बांधी थी। वैसे
आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आँखों पर पट्टी
बांधकर मोटर साइकल चलाना और चित्र बनाना जाडूगरों
का काम है न्यायधीश ये नहीं कर सकते। नेता जरूर कर
सकते हैं, कर भी रहे हैं। । बहरहाल मुख्य न्यायाधीश को
इस तब्दीली के लिए तहेदिल से बधाई। कम से कम
सेवनिवृत्ति से पहले वे भी एक नया इतिहास लिखकर जो
जाने वाले हैं। अब पुरानी हिंदी फिल्मों में दिखाए जाने वाले
अदलातों के इस प्रतीक चिन्ह का क्या होग। राम जाने ?

संपादकीय

सकारात्मक पहल

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों के हित में 'अर्न व्हाहिल लन' योजना शुरू कर रहा है जिसमें वे अपनी नियमित पढ़ाई के दौरान कमाई भी कर सकेंगे। विश्वविद्यालय छात्रों को विभिन्न माध्यमों में स्लैन इंटर्नशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप आदि से कमाने का मौका देगा। इसके लिए डियूयोजन का प्रत्येक विभाग उद्योग आदि की मदद से कॉर्पस फंड जनरेट करेगा। विभाग विभिन्न एजेंसियों के साथ करार करेगा ताकि छात्रों को इनमें इंटर्नशिप मिल सके। पार्ट टाइम जॉब के लिए स्थानीय व्यापार संस्टनों को भी जोड़ेगा। प्रिसिपल इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत छात्रों को मानदेय दिया जाएगा। जरूरतमंद छात्रों को टीचर असिस्टेंटशिप दिए जाने की योजना पर भी जोर रहेगा। योजना का प्रारूप निश्चित रूप से बेहद सकारात्मक प्रतीत हो रहा है। देश भर से छात्र बेहतर भविष्य की तरफ कल्पना के साथ दिविवि में दाखिला लेते हैं जिसमें ढेरों मेंधावी और उत्तम परिश्रमी छात्र ऐसे होते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि कमज़ेर वर्ग से होती है। ये बीते सालों में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह डियू ने भी विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क काफ़ी बढ़ा दिया है। ऐसे में घर-परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करने वालों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इस महणे महानगर में खाने और आवास की व्यवस्था कर पाना उनके लिए बेहद संघर्षपूर्ण होता है। निर्धन देशों में ही नहीं दुनिया भर के अति समृद्ध देशों में भी छात्रों के लिए ऐसी सुविधा होती है जिसमें वे पार्टटाइम काम करने के कुछ पैसा स्वयं कमा सकते हैं। इससे न सिर्फ़ छात्र आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगे, बल्कि उन्हें मिलने वाले इस अनुभव का अतिरिक्त लाभ नौकरियां प्राप्त करने के दौरान में भी मिल सकेंगा। हालांकि अपने यहां पार्टटाइम काम करने के न तो बहुत अवसर हैं, न ही प्रचलन क्योंकि काम से ज्यादा उन्हें करने वाले मौजूद हैं, वह भी बेहद कम मेहनतने पर परंतु ये छात्र प्रशिक्षित होने के साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, इसलिए नियोक्ता को भरपूर मदद मिल सकती है। चूंकि यह काम उन्हें विश्वविद्यालय परिसर या आसपास मिलने की सुविधा होगी तो वे पढ़ाई में अपना वक्त ज्यादा दे सकेंगे। बढ़ती बेरोजगारी और मंहगाई के मद्देनजर यह कदम छात्रों के हित में प्रतीत हो रहा है, हालांकि इससे उनकी पढ़ाई बाधित हाने की आशंका से इकार नहीं किया जा सकता। जितनी संख्या में छात्र हैं, उस अनुपात में जरूरतमंदों को उतना रोजगार दिलाना भी विश्वविद्यालय के लिए कम चनौतीपूर्ण नहीं होगा।

प्रिंटन-मन्त्र

दया करने वालों की जय-जयकार होती है

हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाने के पीछे व्यवहारिकता एवं मानवीय मूल्यों को भलता जा रहा है। रास्ते में अगर कोई मजबूर व्यक्ति दिख जाए तो कोई बैंबसी प्रकट करने के लिए दो पल रुक जाए यहर्व बड़ी बात होती है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी के लिए अपने एक पल और एक रुपए तक खर्च करने में कंजूसी करते हैं। शायद इसलिए कि उन्हें लगता है, भला पीड़ित व्यक्ति उनका क्या नाता है लेकिन ऐसा सोचने से पहले यह शब्द जरूर याद करना चाहिए कि वसुधैव कुटुम्बकम् का मंत्र इस देश ने संसार को दिया है जिसका अथ है वसुधा यानी धर्मते पर रहने वाला हर व्यक्ति हमारा कुटुम्ब है। अगर विष्णु पुराण, श्रीमद्भगवत् पुराण अथवा अन्य कोई भी पुराण उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि हम सभी मनुष्य मनु की संतान हैं। इस नाते हम सभी मनुष्य एक दूसरे के रिश्तेदार हैं।

इस नाते हम सभी को अपने रिश्तेदारों की सहायता करनी चाहिए यहर्व हमारा धर्म है। धर्म ग्रंथों में कहा भी गया है कि दया धर्म का मूल है इसलिए हर व्यक्ति को बिना किसी लालच और स्वार्थ के जरूरत के समय आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनका जयजयकार समाज ही नहीं ईश्वर भी करता है। दया करने वाले व्यक्ति कठिन समय आने पर भी अपना गुण नहीं त्यागता है। इसी कानून उदाहरण है मुगल बादशाह दारा। दारा को औरंगजेब ने बंदी बना लिया बंदी बना दारा जब शहर के बीच से गुजर रहा था तो उसकी स्थिति देखकर लोग तरस खा रहे थे लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। एक फकीर ने दारा की स्थिति को देखकर कहा कि, दारा तो जब भी हाथी पर बैठकर इस रास्ते जाता था तो मेरी झोली भरता था आज क्या फकीर की झोली खाली रहेगी।

दारा ने नजर उठाकर उस फकीर की ओर देखा और अपने शीर पर पड़ा दुशाला उठाकर फकीर की ओर फेंक दिया। दारा की बैंबसी पर जो लोग सिर झुकाए खड़े थे सभी दारा की उदारता और दमालुता को देखकर जयजयकार करने लगे। दारा का झुका हुआ सिर गर्व से ऊपर उठ गया और और औरंगजेब के सैनिकों का सिर शर्म से झुक गया। भले ही आप कर्भंतीर्थ स्थल न जाएं लेकिन जरूरत के समय लोगों की सहायता कर दें तो कई तीर्थ यात्रा का फल आपको घर बैठे मिल जाता है।

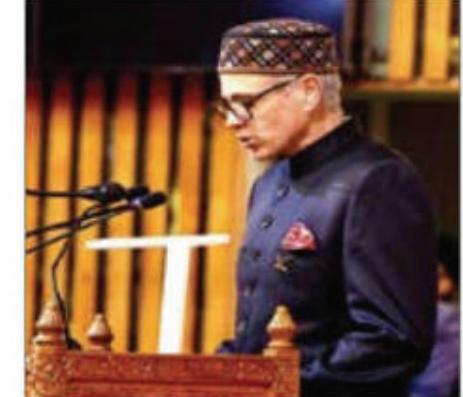
जम्मू - कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार की राहें बड़ी कठिन

धा रा 370 खत्म होने के बाद नेशनल कॉन्स्ट्रक्शन के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित बने जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि, उमर अब्दुल्ला के लिए यह उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अनुच्छेद 370 है और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर का पावर गेम बहुत बदल गया है.. और जम्मू-कश्मीर की राजनीति के लिए यह सबसे अहम पहल है। उमर अब्दुल्ला पहले भी जनवरी 2009 जनवरी 2014 तक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री चुके हैं, उन्हें मुख्यमंत्री होने का तजुर्बा भी है, लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है। उमर अब्दुल्ला एक स्वतंत्र राज्य का सीएम होने का अनुभव लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का सीएम होने का तजुर्बा नहीं है। जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हुआ करते हुए तब जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था और उन्होंने ये केंद्र शासित प्रदेश है। तब जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था, अब बाकी राज्यों तरह ही 5 साल होगा। तब राज्य से जुड़े फैसले तक की सारी शक्तियां विधानसभा और मुख्यमंत्री के पास होती थीं, सारे के सारे कानून बनाने की शक्तियां सीएम के पास होती थीं, लेकिन अब काफी हद तक संघ कंट्रोल उपराज्यपाल के हाथ में होगा। और प्रमुख विधानसभा का सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास होगा, उमर अब्दुल्ला के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। मोदी सरकार का स्वभाव वैसे भी राज्यों में दखल देने का रहा है। जम्मू - कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वायदा करने वाली मोदी सरकार ने आजत बहाल नहीं किया है, जबकि यह नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होता है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि मोदी सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा देती है या लटक रहती है, क्योंकि जम्मू - कश्मीर में हालात कैसे रहते हैं। इस नव गठित सरकार के हाथ में भी रहने वाला है 2019 में धारा 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू-कश्मीर की स्थिति काफी बदल चुकी लेकिन यह भी तय है कि राजनीतिक मरम्भों

बावजूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाती होती रहती है, उसी तरह की तनाती जम्मू-कश्मीर में भी देखने को मिल सकती है। तभी तो कुछ दिन पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक कटाक्ष किया था अगर हाफ स्टेट में सरकार चलाने में दिक्कत आए तो उमर अब्दुल्ला मुझसे सलाह ले सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछले दस सालों से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सीएम केजरीवाल के कटाक्ष के मायने इसलिए भी हैं। क्योंकि कोर्ट से कुछ शक्तियां मुख्यमंत्री को मिली थीं, लेकिन मोदी सरकार उसके विरुद्ध अध्यादेश ले आई थी। ऐसे ही 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक संरचना भी पूरी तरह से बदल गई है और अब वहां सरकार से ज्यादा बड़ी भूमिका उपराज्यपाल की हो गई है। 2019 का कानून कहता है कि पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर जम्मू-कश्मीर विधानसभा बाकी सभी मामलों पर कानून बना सकती है। लेकिन एक पेच भी है। अगर राज्य सरकार राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाती है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे केंद्रीय कानून पर कोई असर न पड़े। इसके अलावा, इस कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी बिल या संशोधन विधानसभा में तब तक पेश नहीं किया जाएगा, जब तक उपराज्यपाल ने उसे मंजूरी न दे दी हो। अब जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल ही एक तरह से सबकुछ है। सरकार को भले ही पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी मामलों में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल का नौकरशाही और एंटी-करप्शन व्यूरो पर भी नियंत्रण होगा। इसका मतलब हुआ कि उपराज्यपाल सरकारी अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग उपराज्यपाल की मंजूरी से होगा। इसके अलावा, उपराज्यपाल के किसी भी काम की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि उन्हें ऐसा करते वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करना

चाहिए था या उन्होंने विवक का इस्तेमाल नहीं किया था। उनके किसी फैसले को अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उन्होंने फैसला ले वक्त मंत्री परिषद की सलाह ली थी या नहीं ली थी। अतः बदल चुके जम्मू - कश्मीर के मुख्यमंत्री की राजनीति आसान नहीं रहने वाली..

कांग्रेस की राजनीतिक चाल ने कश्मीर की नई सरकार के लिए चिंता की लकड़ेर खींच दी है। कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला सरकार को समर्थन तो दिया है लेकिन समर्थन बाहर से दिया है, बाहर से समर्थन देने वाला मतलब है कि कांग्रेस मत्रिमण्डल में शामिल नहीं होगी। उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथग्रहण में कांग्रेस के अध्यक्ष मलिलकार्जुन खड़गे सहित दिग्गज ने राहुल गांधी - प्रियंका गांधी भी शामिल हुए हैं, लेकिन पार्टी ने अपने कोटे से सरकार में किसी को भी मंत्री नहीं बनवाया है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसकी कई वजहें हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बावजूद कांग्रेस उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल नहीं हुई है। कांग्रेस की तरफ से अब्दुल्ला कैबिनेट में कोई भी मंत्री नहीं बना है। वो भी तब, जब कांग्रेस अध्यक्ष मलिलकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद श्रीनगर जाकर सरकार के शपथग्रहण में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के इस फैसले की अब चर्चा हो रही कि आखिर पार्टी ने उमर कैबिनेट में अपने कोटे मंत्री क्यों नहीं दिए? कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसके 4 बड़ी वजहें हैं - जम्मू कश्मीर के चुनावों इतिहास पहली बार कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब है, पार्टी 6 सीटों पर सिमट गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस हार्डिकमान ने पार्टी के किसी विधायक व कैबिनेट में न शामिल कर स्थानीय नेताओं को जर्मनी पर मेहनत करने का संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कोटे से एक भी हिंदू विधायक नहीं जीता है। ऐसे में पार्टी के सियासी समैकरण सध नहीं रहे हैं। कश्मीर का मुस्लिम वोटबैंक पीड़ीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में रहा है। उमर अब्दुल्लाह अंतिम उनकी पार्टी 370 को वापस लाने के पक्ष में है। कांग्रेस



स्टेटहूड की सिर्फ मांग कर रही है। सरकार में पार्टी अगर शामिल होती तो अन्य राज्यों में उसके लिए सियासी बैकफायर कर जाता, इसलिए भी पार्टी ने सरकार में शामिल न होने का फैसला किया है नेशनल कॉम्फ्रेंस के 1-2 मंत्री पद देना चाह रही थी। कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेता सक्रितिक भागीदारी नहीं चाहते थे। 6 विधायक जीते, इनमें 3 दिग्गज कांग्रेस की तरफ से इस बार जम्मू कश्मीर में 6 विधायकों ने जीत हासिल की है। इनमें पीरजादा मोहम्मद सईद, तारिक हामिद कर्गा, गुलाम अहमद मीर जैसे दिग्गज का नाम शामिल हैं। कर्गा घाटी में कांग्रेस के अव्यक्ति हैं। कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना है। कांग्रेस ने घाटी में 37 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जम्मू और चिनाब रीजन में पार्टी पूरी तरह साफ हो गई। अतः कांग्रेस रणनीति है कि इतना औसत प्रदर्शन के बावजूद नेताओं को मंत्री पद मिलना मतलब जमीन से टूट कर सकता है, इंडिया गटबंधन का धर्म निभाने के नाम पर कांग्रेस उमर अब्दुल्ला को समर्थन तो दे रही है, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होना चाहती यह हैरान करने वाला है... बदल चुके जम्मू - कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गाहें आसान नहीं रहने वाली हैं।

-दलाप कुमार पाठक

बेकाबू महंगाई का सितम झेलती जनता

भा रत सहित हिमाचल में इन दिनों हरी सब्जियाँ के दाम आसमान छँ रहे हैं और महां

के दाम आसमान हूँ रह है अर मह सब्जियां आम लोगों की पहुँच से पार चुकी हैं। टमाटर के दाम ने तो सारे स्कॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिमाचल में जहाँ टमाटर 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, वहीं हरा मटर 200 रुपए की दर से बिक रहा है। दूसरी सब्जियां भी 80-90 पार तक बिक रही हैं और सब्जी विक्रेताओं, आढ़तियों व कोई पूछने वाला नहीं है। आलू, प्याज, शिमला मिस्त्री सोने के खाव बिक रहे हैं। एक तरफ शादियों व सीजन चल रहा है, तो दूसरी तरफ त्योहारों के चलने लोगों की जेबें खब ढीली हो रही हैं। सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों के दामों और एमआरपी पर कोई ठोका नियंत्रण न होने के कारण एक तरफ देश में गरीबों व हालत दयनीय होती जा रही है तो वहीं अमीरों व संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में हाल के वर्षों खाद्यान्नों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऊपर से, देश में रोजगार की स्थिति बेहद खराब और लोगों की कमाई भी नहीं बढ़ रही है। इसलिए आम आदमी को पूरा आर्थिक परिहश्य ही नकारात्मक नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाजारों में महंगाई बेलगाम होती जा रही है। ऐसे लगता है जैसे फल एवं सब्जियों के विक्रेताओं में नियम-कायदे और कानूनों का कोई खौफ नहीं है और वे मनमाने दामों पर सब्जियां और फल बेचकर मोटा मुनाफा कमाने जुटे हुए हैं। ऊपर से तुरा यह है कि प्रशासनिक कार्रवाई, जुमाने तथा दंड अथवा लाइसेंस कैसिंस होने का कोई डर न रहने के चलते शायद ही कोई सब्जी, फल विक्रेता अपनी दुकान में इनके दामों व

प्रदर्शित करने वाला बोर्ड लगाने की जहमत उठाता होगा। त्योहारी सीजन के बीच में राष्ट्रीय सार्थकी कार्यालय द्वारा जारी अंकड़ों के मुताबिक खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 5.49 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 3.65 प्रतिशत थी। वहीं सितंबर में थोक महंगाई बढ़कर 1.84 फीसदी पर पहुंच गई है। महंगाई बढ़े? के पीछे खाद्य एवं सब्जियों की कीमतों में वृद्धि मुख्य वजह रही। रिटेल बाजार में खाद्य पदार्थों और सब्जियों के दाम चाहे कितने भी क्यों न बढ़ जाएं, लेकिन किसान वर्ग को इसका फायदा कभी भी नहीं मिलता है। इसके विपरीत जमाखोरों, स्टोरियों द्वारा जमकर खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी की जाती है और बाजार में वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा कर महंगाई को बढ़ाकर चोखा मुनाफा कमाया जाता है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि बढ़ती महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीब एवं मध्यम वर्ग को झेलनी पड़ती है। आज संपन्न नागरिकों को भी चाहिए कि वे वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति से बचें और महंगाई को दूर करने में सरकार का सहयोग करें। पहले से ही कम वस्तुओं को बेकार और बर्बाद न करें, विशेषकर शादियों, घरेलू कार्यक्रमों और धार्मिक उत्सवों में अन्न और सब्जियों की बवादी न करें।

अधिकारियों से उम्मीद है कि वे खाद्य वस्तुओं, विशेषकर फल, सब्जियों की उपलब्धता पर नजर रखने के साथ-साथ उनके दामों को नियंत्रण में रखते हुए सब्जी विक्रेताओं को प्रतिदिन के भावों को लिखकर बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे, ताकि गरीब एवं सामान्य जनता को उनके हाथों से लुटने से बचाया जा सके। इस बात से भी सभी भली-भाति

परिचित ही हैं कि आम आदमी तक खाद्य सामान पहुंचने से पहले दलालों, बिचौलियों और आड़तिकों की जेबें गर्म हो चुकी होती हैं जबकि किसानों व कभी भी उनके उत्पादों के सही दाम नहीं मिलते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन को यह पता ही नहीं है कि बाजारों में सब्जियों के दामों और अन्य खावस्तुओं का क्या हाल है। आज अधिकारी वर्ग अपने कुर्सियों तक सीमित होकर रह गए हैं। आज से 30-35 वर्ष पूर्व जब कभी भी महंगाई का जिन अपने सिर उठाता था तो विपक्षी दलों द्वारा जरूर धरन प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन की खबरें देखने सुनने व मिलती थीं। लेकिन अब जैसे राजनीतिक दलों व आम जनता को हाने वाली परेशानियों से कोई लेनदेना ही नहीं है। मूल्य सूची तो शायद ही कोंडुकानदर लगाता होगा, बिल देना तो दूर की कौम समझिए। बाजारवाद की लृट में अधिकारी व्यापारियों की मौज लगी हुई है और वस्तुओं के मूल्यों पर सरकारी नियंत्रण कर्ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। अग्राहक सरे आम लुट रहा है। क्या आयकर विभाग ऐसे विक्रेताओं की कमाई तथा टैक्स देयता की भी जांच पड़ताल करेगा? प्रश्न यह भी उठता है कि जब देश में जीवनेपयोगी वस्तुओं की बढ़ुताता है तो पिछले मूल्यवृद्धि क्यों और किसान गरीब क्यों? यह सही कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन वैश्विक सहयोग और कई अन्य उपायों से वस्तुओं व उपलब्धता में भी उसी अनुपात में बढ़ोतारी हो रही है तो भी चीजें इतनी महंगी क्यों बिक रही हैं और महंगी का बोलबाला क्यों है?



वस्तुओं का कृत्रिम अभाव कौन पैदा कर रहा है, क्यों सरकारें इन पर लगाम नहीं लगा पा रही हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को भी तो अंततः जनता जनर्दन की कृपा से ही सरकारें बनाने का सुफल मिलता है, तो फिर क्यों वे आम जनता के हितों को नजरअंदाज करते हैं? सरकार को चाहिए कि वह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु आपूर्ति रखरखाव अधिनियम 1980 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करे। अंततः सबल उठता है कि क्या सरकार और अफसरस्थाही के पास इस लूटपाट को अंजाम देने वाले जमाखोरों, मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने का जीतपात्र है?

-अनुज आचार्य (स्वतंत्र लेखक)

